IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.20476 of 2018

==========

Chandra Kishor Ray, Son of Nandlal Ray, Resident of Village-Tetaria, East Champaran.

... ... Petitioner/s

Versus

1. The State of Bihar through the Chief Secretary
2. The Director, Department of Human Resource Development, Govt of Bihar, Patna.
3. The Principal Secretary, Department of Education, Govt. of BIhar, Patna.
4. The Director, Mass Education, Govt of BIhar, Patna.
5. The Director, Elementary Education, Govt. of Bihar, Patna
6. The Director, Secondary Education, Govt. of Bihar, Patna
7. The Director, Bihar Education Project Council, Govt. of Bihar, Patna.

... ... Respondent/s

==========

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Ashok Kumar Chaudhary, Advocate
Ms.Anju Mishra, Advocate
Ms. Roona (*Amicus Curiae*)

For the Respondent/s : Smt.Shilpa Singh -GA12
Ms. Abhanjalli, AC to GA 12

==========

CORAM: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE
and
HONOURABLE MR. JUSTICE S. KUMAR
ORAL JUDGMENT

(Per: HONOURABLE THE CHIEF JUSTICE)

Date : 25-01-2021

Petitioner has prayed for the following relief(s):-

"a. For directing the respondent authorities to disengage the Key Resource Persons (KRPs) and the State Resource Group (SRGs) with immediate effect, who are deployed from amongst the govt. elementary and middle school teachers to

WEB COPY

monitoring the Akshar Anchal Yojana of the govt of Bihar.

b. For directing the respondent authorities not to engage the primary and middle school teachers of the Govt. schools in non academic works, other than those specified in section 27 of the RTE Act 2009.

c. For issuance of any other appropriate writ/s, order/s or direction/s as the Hon'ble Court may deem fit and necessary in the facts and circumstances of the case."

With the intervention of the Court, thankfully, the Government has now taken a decision taking remedial measures, which is evident from communication dated 19.01.2021. The said communication is reproduced as under:-

WEB COPY

ईमेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक:-7/विविध-35/2015 अंश 'क' 76

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डॉ० रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

सेवा में,

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 19/01/2021.

विषय:- सरकारी विद्यालय के शिक्षकों से अन्यत्र कार्य नहीं लेने के संबंध में एवं सभी प्रतिनियुक्ति रद्द करने के संबंध में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-780 दिनांक-07.06.2013 एवं पत्रांक-1068 दिनांक-22.09.2016 का कृपया निदेश किया जाय। उक्त पत्र के द्वारा बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 अप्रैल 2010 से प्रभावी है कि अधिनियम की धारा 27 के आलोक में निदेशित है कि कोई भी शिक्षक दशवर्षीय जनगणना, आपदा सहायता तथा विधान मंडल, संसद एवं स्थानीय निकाय के चुनाव को छोड़कर अन्य किसी भी गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किये जायेगें। इस क्रम में भारत सरकार द्वारा भी यह निदेशित किया गया है कि चुनाव संबंधी कार्य यथा प्रशिक्षण, चुनाव सामग्रियों की प्राप्ति, मतदान एवं मतगणना से संबंधित कार्य शिक्षण के लिए निर्धारित कार्य दिवसों/सामग्रियों में किये जा सकते है, लेकिन मतदाता सूची के निर्माण/पुनरीक्षण का कार्य गैर शैक्षणिक कार्य दिवसों, अवकाश एवं छुट्टियों के दिन में ही किया जाय अर्थात मतदाता सूची से संबंधित किसी भी कार्य का प्रभाव शिक्षक के शैक्षणिक गतिविधियों पर न पड़े।

हाल में अनौपचारिक सूत्रों से सूचनाये प्राप्त हो रही है कि स्पष्ट निदेश के बावजूद स्थानीय स्तर पर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा या अन्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति स्थानीय-स्तर-पर की जाती है।

अतः यदि आपके जिलान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों का कोई शिक्षक अद्यावधि प्रतिनियुक्ति पर हो तो उनकी प्रतिनियुक्ति अविलम्ब रद्द किया जाय एवं उक्त निर्देश का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन दिनांक-22.01.2021 तक अचूक रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ० रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक, प्राथमिक शिक्षा।

The teachers who were appointed as Key Resource Persons (KRPs) at the district level State Resource Groups (SRGs) have been withdrawn and directed to impart education to the children in terms of the statutory mandate for the Right to Children to Free and Compulsory Education Act, 2009.

In view of the aforesaid, we close the present

WEB COPY

proceedings leaving it open for the petitioner as also learned *Amicus Curiae* to agitate collateral issues before the appropriate forum, if so required and desired.

We place on record the efforts put in by Ms. Roona, learned *Amicus Curiae*, in assisting the Court.

(Sanjay Karol, CJ)

(S. Kumar, J)

sujit/-

AFR/NAFR	
CAV DATE	
Uploading Date	27.01.2021
Transmission Date	

WEB COPY